

## Civil Services (Main) Examination, 2024

PHKM-U-LAW

## विधि (प्रश्न-पत्र-I)

निर्धारित समय : तीन घण्टे

अधिकतम अंक : 250

## प्रश्न-पत्र सम्बन्धी विशेष अनुदेश

(कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़िए)

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द-सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।

प्रश्नों के प्रयासों की गणना क्रमानुसार की जाएगी। यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो। प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू० सी० ए०) पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप में काटा जाना चाहिए।

## LAW (PAPER-I)

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 250

## QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

(Please read each of the following instructions carefully before attempting questions)

There are EIGHT questions divided in two Sections and printed both in HINDI and in ENGLISH.

Candidate has to attempt FIVE questions in all.

Question Nos. 1 and 5 are compulsory and out of the remaining, THREE are to be attempted choosing at least ONE question from each Section.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.

## खण्ड—A / SECTION—A

1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

(a) उच्च न्यायालयों से आपराधिक मामलों में आने वाली अपीलों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय की अपीलिय अधिकारिता का परीक्षण कीजिए।

Examine the appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in regard to criminal matters.

(b) संसद अथवा किसी राज्य विधायिका को अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में ही रहना चाहिए तथा अन्यो के विषयक्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

The Parliament or any State Legislature should keep within the domain assigned to it and not encroach upon the other's subject. Critically examine.

(c) "प्रत्येक व्यक्ति, जो संघ की सिविल सेवा का सदस्य है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारित करता है।" क्या इस नियम का कोई अपवाद है? वर्णन कीजिए।

"Every person who is a member of civil service of the Union holds office during the pleasure of the President." Is there any exception to this rule? Describe.

(d) भारतीय संविधान प्रत्यायोजन की अनुमति तो देता है, लेकिन साथ ही मूल विधि से सरेखण एवम् विधायी आशय को सुरक्षित रखने हेतु विशेष प्रतिबन्ध भी आरोपित करता है। दृष्टान्तों की सहायता से परीक्षण कीजिए।

The Indian Constitution permits delegation but imposes specific restrictions to ensure alignment with the Parent Act and protect legislative intent. Examine with illustrations.

(e) "सुसंगत मूलभूत अधिकार के उल्लंघन में अथवा असंगत होने की सीमा तक ही कोई विधि शून्य होगी।" निर्णीत वादों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

"A law is void only to the extent of inconsistency or contravention with the relevant Fundamental Right." Explain with the help of decided cases.

2. (a) लोक हित वाद की अवधारणा 'लोकस स्टैन्डी' के नियम का अपवाद है। भारत में अग्रणी वादों की सहायता से इसके विकास, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के सन्दर्भ में विस्तारित कीजिए। इसकी कमियों का भी वर्णन कीजिए।

The concept of Public Interest Litigation is an exception to the rule of 'locus standi'. Elaborate in the light of its evolution, aims and objects in India with the help of leading cases. Also discuss its drawbacks.

20

(b) "संविधानवाद एक मूल विधि के अन्तर्गत सीमित शासन की अवधारणा है।" इसके आलोक में, संविधान तथा संविधानवाद की सुस्पष्ट विशेषताओं के मध्य अन्तर स्थापित कीजिए।

"Constitutionalism is the concept of limited government under a Fundamental Law." In the light of this, differentiate between distinctive features of Constitution and Constitutionalism.

15



- (c) भारत में संसदीय शासन-प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद् के मध्य सम्बन्धों की विवेचना कीजिए। सुसंगत संवैधानिक प्रावधानों की सहायता से स्पष्ट कीजिए।

Discuss the relationship between the President and the Council of Ministers under the parliamentary form of government in India. Explain with the help of relevant constitutional provisions.

15

3. (a) “अनुच्छेद 194, जो कि अनुच्छेद 105 का सटीक प्रत्युत्पादन है, राज्य विधायिकाओं तथा उनके सदस्यों एवम् समितियों से सम्बन्धित है।” इस पृष्ठभूमि में टिप्पणी कीजिए कि ये दोनों ही अनुच्छेद एक-दूसरे के पूरक हैं तथा इन्हें साथ-साथ पढ़ा जाना चाहिए।

“Article 194, which is an exact reproduction of Article 105, deals with the State Legislatures and their members and committees.” On this background, comment that both the Articles are complementary to each other and should be read together.

20

- (b) ‘अल्पसंख्यक’ कौन हैं? भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा हितों को उस सीमा तक संरक्षित करता है कि उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा प्रशासित करने के प्रदत्त अधिकार आत्यंतिक नहीं हैं तथा युक्तियुक्त प्रतिबन्धों के अधीन हैं। निर्णीत वाद विधि की सहायता से विवेचना कीजिए।

Who are ‘minorities’? The Constitution of India protects the rights and interests of minorities to the extent that the rights conferred to them to establish and administer educational institutions of their choice are not absolute and are subject to reasonable restrictions. Discuss with the help of decided case laws.

15

- (c) संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध भी है? अपने उत्तर के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के सुसंगत निर्णय भी लिखिए।

Discuss the procedure of amending the Constitution. Are there any restrictions also in this regard? Support your answer with the help of relevant Supreme Court judgments.

15

4. (a) हाल के वर्षों में ‘सहकारी संघवाद’ की अवधारणा ने राष्ट्र के संवैधानिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, परन्तु साथ ही इसे विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। विस्तारित कीजिए।

In recent years, the concept of ‘Cooperative Federalism’ has played a pivotal role in constitutional governance of the nation but at the same time it comes across various challenges as well. Elaborate.

20

- (b) “मूलभूत अधिकार अपने आप में साध्य नहीं हैं, बल्कि साध्य के साधन के रूप में हैं। साध्य निदेशक तत्त्वों में विनिर्दिष्ट किया गया है।” उक्त कथन का विश्लेषण कीजिए।

“The Fundamental Rights are not an end in themselves but are the means to an end. The end is specified in the Directive Principles.” Analyze the statement.

15

- (c) “राष्ट्रपति तथा राज्यपालों की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान की एक अनन्य विशेषता है, लेकिन यह व्यावहारिक शासन तथा संभावित अतिसन्धान के बीच धारदार सन्तुलन पर टिकी हुई है।” निर्णीत वाद विधि की सहायता से आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

“The ordinance making power of the President and the Governors is a unique feature of the Indian Constitution but it balances on a razor-sharp edge between pragmatic governance and potential over-reach.” Critically examine with the help of decided case laws.

15

### खण्ड—B / SECTION—B

5. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Answer the following questions in about 150 words each :

10×5=50

- (a) अन्तर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए। इसकी कमियों को इंगित कीजिए तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव दीजिए।  
Define International Law. Enumerate its weaknesses and give suggestions for improvement.
- (b) राज्य मान्यता क्या है? विधितः (डी जुरे) मान्यता तथा वस्तुतः (डी फैक्टो) मान्यता के मध्य अन्तर स्थापित कीजिए।  
What is State recognition? Draw a distinction between recognition de jure and de facto.
- (c) राष्ट्रियता के महत्त्व का परीक्षण कीजिए तथा राष्ट्रियता के अधिग्रहण के तरीकों का वर्णन कीजिए।  
Examine the importance of nationality and discuss the modes of acquisition of nationality.
- (d) राज्यक्षेत्रीय समुद्र तथा अन्तर्देशीय जल की अवधारणा के मध्य अन्तर स्थापित कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत राज्यक्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई पर टिप्पणी कीजिए।  
Distinguish between the concept of territorial sea and inland water. Comment on the breadth of territorial sea that is internationally accepted.
- (e) संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग के रूप में ‘आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्’ के महत्त्व का परीक्षण कीजिए।  
Examine the importance of ‘the Economic and Social Council’ as a principal organ of the United Nations.

6. (a) अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध एवम् परस्पर सहयोग संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धान्तों पर विकसित हुआ है। व्याख्या कीजिए।

Peaceful settlement of international disputes has been developed on the principles of International Law concerning friendly relations and cooperations among States. Explain.

20



- (b) वर्तमान विश्व 'आर्थिक व्यवस्था', मुक्त बाजार शक्तियों द्वारा संचालित, मुक्त प्रतिस्पर्धा द्वारा उद्वेलित तथा वस्तुओं एवम् सेवाओं के मुक्त संचालन, जिसमें तकनीकी भी सम्मिलित है, पर आधारित उद्यमों द्वारा अनुमित किया जाता है। स्पष्ट कीजिए।

The present world 'Economic Order' is supposed to be granted by the operation of free market forces propelled by free competition and enterprises, based on free movement of goods and services including technology. Elucidate.

15

- (c) अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवम् राष्ट्रीय विधि, विधि के एकीकृत ज्ञान की दो शाखाएँ हैं, जो कि मानव समुदाय पर किसी-न-किसी रूप से लागू होती हैं। प्रचलित सिद्धान्तों की सहायता से विस्तारित कीजिए।

International Law and Municipal Law are two branches of unified knowledge of law, which are applicable to human community in some way or the other. Elaborate with the help of prevalent theories.

15

7. (a) 'द्वितीय विश्व युद्ध' में हुए विनाश के उपरान्त विश्व में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित किए जाने हेतु आर्थिक पुनःप्राप्ति को बढ़ावा देने एवम् एक वैश्विक मौद्रिक प्रणाली का निर्माण करने के लिए विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दो ऐतिहासिक संस्थानों, का अभ्युदय हुआ। विस्तृत वर्णन कीजिए।

Following 'World War II' destruction, the World Bank and the International Monetary Fund emerged as two historic institutions to promote economic recovery and to build a global monetary system to ensure economic stability around the world. Discuss at length.

20

- (b) प्रत्यर्पण सम्बन्धी विधि का वर्णन कीजिए। शरण देने की प्रक्रिया और प्रत्यर्पण आवेदन की मंजूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भिन्नता है। व्याख्या कीजिए।

Discuss the law on extradition. The procedure for granting asylum and approving extradition requests differ significantly. Explain.

15

- (c) हस्तक्षेप क्या है? मानवीय आधारों पर हस्तक्षेप तथा आत्म-प्रतिरक्षा के कारण हुए हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए। What is intervention? Discuss the intervention on humanitarian grounds and the intervention due to self-defence.

15

8. (a) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की 'आतंकवाद-विरोधी समिति' के गठन का वर्णन कीजिए। अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आतंकवाद का मुकाबला करने में यह समिति किस सीमा तक प्रभावी रही है? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

Describe the constitution of United Nations Security Council's 'Counter-Terrorism Committee'. To what extent has this Committee been effective in countering terrorism across international borders? Critically analyze.

20

- (b) परमाणु निरस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या आपकी राय में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि (सी० टी० बी० टी०) अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

What do you understand by nuclear disarmament? Do you agree with the opinion that Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) has been successful in achieving its objects? Critically examine.

15

- (c) विराष्ट्रिकता क्या है? एक राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति को प्रायः अनेक मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना करना पड़ता है। विराष्ट्रिकता के कारण व्यक्ति को किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? विराष्ट्रिकता से सम्बन्धित मानवाधिकार के मुद्दों को विस्तार से समझाइए।

What is statelessness? A stateless person is often subjected to a number of human rights violation. What are the impediments that people face due to statelessness? Elaborate the human rights issues that are connected to statelessness.

15

\*\*\*

